हरियाणा की राजनीतिक डायरी....

इनैलो के अभय चौटाला मायावती से राखी बंधवाने क्या पहुंचे, शुरू हुई नई चर्चा

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

नई दिल्ली: इंडियन नैशनल लोकदल (इनैलो) के सीनियर नेता अभय चौटाला रक्षा बंधन वाले दिन बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती से राखी बंधवाने पहुंचे तो इस पर पूरे हरियाणा की नजर गई। मई 2018 में जब इनैलो और बसपा ने चुनावी गठबंधन किया था, तब इसकी इतनी चर्चा नहीं हई थी लेकिन मायावती की राखी ने इस गठबंधन की चर्चा करा दी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कान पहले खड़े हुए।

यह राजनीतिक रक्षाबंधन था। हरियाणा में खोई जमीन वापस पाने को बेकरार इनैलो जानती है कि मायावती के धागों की ताकत उसे सत्ता के गलियारों तक पहुंचा सकते हैं। राजनीतिक रक्षाबंधन के सामने आने के बाद सभी ने जेल में बंद ओमप्रकाश चौटाला की सियासत का लोहा माना कि दिशा ठीक है, नतीजा क्या निकलता है। भविष्य में तय होगा।

लाजवाब समीकरण

हरियाणा में जाट और दलित अगर मिलते हैं तो यह लाजवाब सियासी समीकरण होगा और नतीजा देकर जाएगा। हरियाणा की ढाई करोड़ से कुछ ज्यादा आबादी में दलित वोटर 20 फीसदी हैं। इसमें जाट मतदाता करीब 29 फीसदी हैं। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से करीब 40 सीटें ऐसी हैं जहां बसपा का वोट शेयर 7 से 8 फीसदी है। विधानसभा की 60 सीटें ऐसी हैं, जहां जाट मतदाता सबसे ज्यादा हैं। इनैलो यह मानकर चल रही है कि इस बार करीब 29 फीसदी जाट वोट उसे मिल सकता है। क्योंकि बहुत मुमकिन है कि कांग्रेस किसी जाट चेहरे को आगे कर चुनाव नहीं लड़ेगी। इन हालात में इनैलो जो घोषित रूप से जाट पार्टी कहलाती है, उसे इसका सीधा फायदा होगा। हरियाणा में 37-38 फीसदी वोट हासिल करने वाली पार्टी आसानी से सरकार बनाने की स्थिति में होगी। ऐसा नहीं है कि दोनों पार्टियों ने ऐसा प्रयोग पहले नहीं किया है। 1998 के लोकसभा चुनाव में इस गठबंधन को दस में से पांच सीटें मिली थीं। इसमें इनैलो की चार सीटें आईं थीं और बसपा को एक सीट मिली थी। तब यह पार्टी हरियाणा लोकदल (राष्ट्रीय) के नाम से जानी जाती थी। उसने बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था।

क्या होगा यह मिलन

राजनीतिक विश्लेषक इस गठजोड़ को तमाम सवालों के नजरिए से देख रहे हैं। उनमें से एक ने कहा कि हरियाणा में सब साथ हो सकते हैं लेकिन जाट-दलित कभी भी एक प्लैटफॉर्म पर नहीं आ सकते। दोनों एक दूसरे के घोर विरोधी हैं और ठीक से देखना तक पसंद नहीं करते। हालांकि एक अन्य राजनीतिक विश्लेषक का कहना है कि इस वक्त चौटाला खानदान की नैया डूबी हुई है, उसे बचाने को वह दलितों को गले लगा सकते हैं। अगर चौटाला खानदान दलितों को गले लगाता है तो जाट दलितों की एकता हरियाणा में नया गुल खिला सकती है।

क्या सैनी कुछ कर पाएगा

हाल ही में पानीपत में भाजपा सांसद राजकुमार सैनी ने राज्य के दलितों को एक मंच पर लाने के लिए एक दलित पार्टी की घोषणा की गई है। सैनी को भाजपा अपना असंतुष्ट सांसद बताती है लेकिन वह अपनी राजनीतिक समझ को परिपक्व नहीं बना पा रही है। राजकुमार सैनी की पानीपत रैली बेशक फ्लाप हो गई हो लेकिन दलितों की नई पार्टी का ऐलान तो उन्होंने कर दिया है। राजनीतिक विशलेष्कों का कहना है कि सैनी को दलितों को एकजुट करने की जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा की यह योजना फूट डालो और राज करो के हिसाब से है और इनैलो और बसपा गठबंधन के मद्देनजर बनाई गई है। भाजपा को सैनी से उम्मीद है कि हरियाणा का दलित और ओबीसी राजकुमार सैनी के कहने से वोट डालेगा।

खुद अपना प्रबन्धन नहीं कर सकता डीएवीआईएम, छात्रों को क्या पढ़ायेंगे

फ़रीदाबाद (म.मो.) गतांक में सुधी पाठकों ने पढा था कि एनएच-3 स्थित प्रबन्धन की पढाई पढाने वाले डीएवी कॉलेज में कितने बड़े पैमाने पर घोटाले चल रहे हैं। इससे लगता है कि वहां केवल घोटाले करने की ही विद्या सिखाई जाती होगी। जहां तक छात्रों का प्रबन्धन की पढाई पढाने का सवाल है तो उसमें तो यह कॉलेज खुद ही फ़ेल है तो औरों को क्या पढायेगा?

एआईसीटीई (ऑल इंडिया काऊंसिल ऑफ़ टेक्निकल एजुकेशन) की धमकी के बाद कॉलेज के प्रबन्धकों ने कॉलेज के लिये प्रिंसिपल पद के लिये एक लाख रुपये खर्च करके दो बड़े अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित करा कर इस पद के लिये योग्य अभ्यार्थियों से आवेदन आमंत्रित किये। नियमानुसार यह आमन्त्रण डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के प्रधान की ओर से होना चाहिये था और आवेदक को आवेदन की एक प्रति सीधे एमडी युनिवर्सिटी रोहतक को भेजने के लिये कहा जाना चाहिये था। लेकिन प्रबंधन का पाठ पढ़ाने वाले प्रबन्धकों को इन दोनों ही बातों का ज्ञान नहीं था; लिहाजा युनिवर्सिटी ने विज्ञापन रद्द कर दिया।

इस प्रबन्धकों ने एक लाख रुपये खर्च करके दोबारा विज्ञापन छपवाया जिसमें प्रबन्धन समिति के प्रधान की ओर से आवेदन आमन्त्रित किये गये थे। लेकिन अपनी अयोग्यता के चलते प्रबन्धकों ने इसमें एक लाइन यह जोड़ दी थी कि जो अभ्यार्थी पहले आवेदन कर चुके हैं, उन्हें पुन: आवेदन करने की जरूरत नहीं। इस पर यूनिवर्सिटी ने एतराज जताते हुये लिखा कि उन्हें क्या पता कि पहले किस-किस ने आवेदन किया है? लिहाज़ा इसी बात पर यह दूसरा विज्ञापन भी रद्द हो गया और संस्था के दो लाख गये पानी में।

अब तीसरी बार पुन: एक लाख खर्च करके तीसरी बार विज्ञापन छपवाया गया है। फ़िलहाल इस पर किसी प्रकार के एतराज की सूचना नहीं है। इसलिये यह समझा जा रहा होगा कि यह सही ही होगा। इसके आधार पर अब प्रिंसिपल की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। प्रबन्धकों के इस कुप्रबन्धन के चलते संस्था को तो दो लाख की हानि हुई सो हुई, अभ्यार्थियों के बीच कितना असमांजस्य हुआ उसका आंकलन करना कठिन है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर अभ्यार्थी इनके तीनों विज्ञापन को पढ पाया होगा।

इतना ही नहीं यह कुप्रबन्धन तब हो रहा है जब एआईसीटीई ने बड़ी मुश्किल से इन्हें 12 अक्तूबर तक प्रिंसिपल नियुक्त करने का समय दिया हुआ है। ऐसे में नियुक्ति एवं चयन प्रक्रिया पूरी कर पाना आसान नहीं होगा।

नीलम गुलाटी के लिये एमडीयू प्रशासन तक को खरीद लिया

डीएवी कॉलेज प्रबन्धन समिति में अपनी दादागिरी चलाने वाले प्रबोध महाजन ने नीलम गुलाटी को पहले प्रोफ़ेसर फिर प्रिंसिपल बनाये रखने के लिये एमडी युनिवर्सिटी प्रशासन तक को खरीदने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी। इसी युनिवर्सिटी ने अपने तय मानकों के अनुरूप नीलम गुलाटी की योग्यता न पाकर पहले उनके लेक्चरार पद को मंजूरी नहीं दी थी, परन्तु बाद में सौदेबाजी हो जाने पर दे दी थी।

इसी बात को लेकर हरियाणा विधानसभा सभा के स्पीकर को दी गई एक शिकायत के आधार पर इस (एमएवीआईएम) कॉलेज की जांच करने एमडीयू से बाकायदा एक जांच कमेटी आई थी। इसमें, प्रोफ़ेसर एस एस दहिया, प्रोफ़ेसर केवी चमार तथा कॉलेजों के इन्चार्ज सत्यनारायण शर्मा सदस्य थे। इन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट में नीलम गुलाटी को तो पूरी तरह से अयोग्य ठहराया ही साथ में इस कॉलेज में चल रही अनेकों अनियमितताओं व फ़ीस के ढांचे का भी उल्लेख किया था।

इस कमेटी द्वारा 17 सितम्बर 2015 को तैयार की गयी इस, तथ्य उजागर करने वाली रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही करने की बजाय भ्रष्ट युनिवर्सिटी प्रशासन इस पर कुंडली मार कर बैठ गया। युनिवर्सिटी के इस रवैये को देखते हुये एक नागरिक ने स्थानीय सैशन कोर्ट में एक याचिका जून 2018 में दायर की। इस पर न्यायालय ने जुलाई में युनिवर्सिटी के नाम नोटिस जारी करके पूछा कि उक्त रिपोर्ट पर अभी तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई?

खाया, पीया-अघाया प्रशासन इस पर चुप्पी साधे बैठा है और तारीख पर तारीख लेकर अपना मुंह छिपाये है। ऐसी ही एक तारीख पेशी 7 सितम्बर को भी लगी थी। इस पर भी एमडीयू की ओर से जब कोई जवाब नहीं आया तो न्यायालय ने तीन अक्तूबर की तारीख पेशी लगाते हुये स्वयं सहायक रजिस्ट्रार को कोर्ट में हाजिर आने का आदेश दिया।

दरअसल आजकल इस तरह की युनिवर्सिटियों में इस तरह के रजिस्ट्रारों के पल्ले अधिक कुछ रहा नहीं है, सब कुछ वाइस चांसलर ने अपनी मुट्ठी में रखा होता है। मौजूदा वीसी पूनिया में इस पद के लिये कोई योग्यता न होने के बावजूद राजनीतिक भ्रष्टाचार के आधार पर इन्हें यह नियुक्ति मिली हुई है। पूनिया ही नहीं इनसे पूर्व रहे वीसी रामफ़ल को भी तत्कालीन मुख्यमंत्री हुड्डा की चरणवंदना के आधार पर ही नियुक्ति मिली थी। इस तरह नियुक्ति पाये वाइस चांसलरों से भ्रष्टाचार फ़ैलाने के अलावा और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? इनसे उम्मीद के अनुरूप ये पूरी शिक्षा व्यवस्था का बंटाधार करने में जुटे हैं।

एनएचपीसी का रेलवे अंडरपास बना जनता की मुसीबत

फ़रीदाबाद (म.मो.) राष्ट्रीय राजमार्ग से ग्रीन फ़ील्ड कॉलोनी व आनंगपुर गांव को सीधे जोड़ने के लिये एनएचपीसी चौक पर रेलवे अंडरपास बनाया गया था। तीसियों वर्ष पुराने इस अंडरपास से बरसातों के मौसम में गुजरना न केवल दुभर हो जाता है बल्कि कई बार जान लेवा भी हो जाता है। गत दसियों वर्ष में कम से कम यहां 15 लोग जान गंवा चुके हैं।

पानी की निकासी व्यवस्था न होने के चलते जरा सी बरसात में यह लबालब पानी से भर जाता है। कई बार अनजाने में गाड़ियां इसमें घुस कर डूब चुकी है। पैदल चलने वाले लोग ऐसी स्थिति में पुल के ऊपर से रेलवे लाईन को पार करते हुये अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी सोमबार (3 सितम्बर) को एक राहगीर रेलवे लाईन पार करते वक्त गाड़ी की चपेट में आ गया। जान तो बच गयी परंतु उसका एक हाथ कट गया। हर हादसे के बाद सरकार एवं नगर निगम जल निकासी की व्यवस्था दुरूस्त करने का आश्वासन तो देते हैं परंतु धरातल पर कुछ नहीं करते।

पिछले दिनों, करीब दो वर्ष पूर्व यह मामला मुख्यमंत्री खट्टर के नोटिस में भी लाया गया। इसके बाद जल निकासी के लिये वहां 'शक्तिशाली' पम्प लगाया गया और एक पम्प ऑपरेटर की नियुक्ति की गयी। लगता है कि जैसी निकम्मी सरकार है वैसा ही निकम्मा प्रशासन है और इन दोनों से कहीं अधिक निकम्मा पम्प और इसका ऑपरेटर हैं। लगता है सब कुछ कागज़ों में ही हो रहा है। असली बिल बनाकर पैसे खाये जा रहे हैं और नकली पम्प व ऑपरेटर लगाये गये हैं। लोग मरते हैं तो मरें, शासन-प्रशासन की बला से।

यदि सरकार की नियत वास्तव में ही समस्या का समाधान करने की होती तो पम्प व ऑपरेटर की ड्रामेबाज़ी करने की बजाय इसका सस्ता स्थाई समाधान हो सकता है। विदित है कि अंडरपास से मात्र 50 मीटर की दूरी पर बुढिया नाला है। यदि एक नाली खोदकर अंडरपास को बुढिया नाला से जोड़ दिया जाय तो बरसात का पानी स्वत: बह कर बुढिया नाले के माध्यम से निकल सकता है। इसके लिये यदि आवश्यक हो तो बुढिया नाले को भी दो-तीन फ़ीट गहरा किया जा सकता है। परन्तु यह सब तो कोई तब करे न जब किसी को जनता के सुख-दुख से कोई सरोकार हो।

गुड़गांव सिटी बस सेवा: खट्टर की हरी झंडी को लाल ही मानो

फ़रीदाबाद (म.मो.) यहां तो अभी सिटी बस सेवा चलाने की योजना बन ही रही है लेकिन बीते सप्ताह मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हड़ी झंडी दिखाकर गुड़गांव बस सेवा का उद्घाटन कर दिया।

गतांक में '**मज़दूर मोर्चा**' ने बीते करीब छ: वर्षों में सिटी बस की दुर्दशा का विवरण प्रकाशित किया था। इसकी जो दुर्दशा फ़रीदाबाद में हुई थी लगभग वही दुर्दशा गुड़गांव में भी हुई। जिस प्रकार जेएनयूआरएम (जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन) के तहत सिटी सेवा के लिये 200 बसें फ़रीदाबाद को दी थी उसकी तरह करीब 200 बसें गुड़गांव को भी दी थी। जिस तरह अब खट्टर जी हड़ी झंडी दिखाकर सिटी बस सेवा का उद्घाटन कर रहे हैं और फ़रीदाबाद में भी करने की सोच रहे हैं, यही काम करीब 6 वर्ष पूर्व तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा भी कर चुके हैं। इसके उद्घाटन समारोहों में शोभा एवं भीड़ बढ़ाने के लिये चंडीगढ तक से दर्जनों उच्चाधिकारी आते हैं, जाहिर है इस पर सरकारी खजाने का भारी दुरूपयोग होता है।

इसमें कोई दो राय नही कि बढते शहरी क्षेत्र के निवासियों को सस्ते एवं शुलभ सार्वजनिक परिवहन की सख्त जरूरत है। लेकिन जनता की इस आवश्यकता के नाम पर ये सियासी लोग जो ड्रामेबाज़ी कर रहे हैं उससे जनता को कोई दूरगामी लाभ होने वाला नहीं है बल्कि जनता के खून-पसीने की कमाई को इन ड्रामेबाजियों पर बर्बाद किया जा रहा है।

सिटी बस सेवा अपने आप में कोई नया अजूबा नहीं है जिसके लिये मुख्यमंत्रियों को आकर झंडियां दिखानी पड़े। जनता की जरूरतों के अनुरूप हरियाणा राज्य परिवहन कभी से ही सिटी बस सेवायें देता आ रहा है। 1964 में जब इस विभाग ने रोहतक वासियों की इस जरूरत को समझा तो सिटी बस सेवा शुरू कर दी गयी थी। पहली सिटी सेवा मुख्य बस अड्डे (भिवानी स्टैंड)से लेकर मेडिकल कॉलेज तक चलाई गयी थी, जिसका बाद में जरूरत के अनुसार विस्तार किया जाता रहा। इसी तरह हिसार शहर में भी 1960 के दशक में सिटी बस सेवा शुरू कर दी गयी थी। फ़रीदाबाद में भी यह सेवा 1970 के दशक में चालू थी लेकिन भ्रष्ट एवं निकम्मी सरकारों के कुप्रबन्धन के चलते चली-चलायी बस सेवाओं की तो दुर्दशा कर दी गयी और अब झंडियां दिखाने की ड्रामेबाज़ी कर रहे हैं।

बात करने का वक्त नहीं, पुलिस है न लाठियां मारने को!

फ़रीदाबाद (म.मो.) 26 दिनों से धरना प्रदर्शन करने वाले छात्रों की मांगों को मानना या सुनने का वक्त शहर को स्मार्ट बनाने में जुटे भाजपा नेताओं के पास नहीं है। उनकी इस मांग पर कि प्रशासन से कोई तो आये, इसके लिए पुलिस आई और लाठी डंडों के साथ आई। तेल पिलाई लाठियों ने छात्रों की मांगो को चूरा करते हुए उनकी हड्डियाँ तोड़ डाली।

एनएसयूआई छात्र नेता कृष्ण अत्री ने बताया कि नागरिकों की रक्षा में जुटी पुलिस और साथ में लड़कियों की सुरक्षा का बीड़ा उठाये दुर्गा शक्ति वाहिनी दल के लोगों ने छात्रों को पीटा और लड़कियों को बालों से घसीटते हुए यहाँ-वहाँ फेका। अत्री के अनुसार, पुलिस के बर्ताव के चलते धरना भी वापस नहीं लिया गया। जहाँ एक तरफ सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने छात्रों पर हुए इस बर्बरता की राजनाथ सिंह स्टाइल में निंदा कर कोरम पूरा किया वहीं कांग्रेस के स्थानीय नेता भी अपनी छात्र विंग के समर्थन में खड़े नहीं हो पा रहे। इन राजनीतिक मेंढकों के पास अपने ही समर्थक छात्रों के साथ अस्पताल जाने तक का समय नहीं। ध्यान रहे छात्रों को पीटने के बाद उनका मेडिकल तक नहीं कराया गया।

सरकार, लोकतंत्र में तानाशाही का तड़का लगा उसकी खुशबू की बेखुदी में बहकी हुई है। कृष्णपाल गुर्जर, विपुल गोयल, मूलचंद जैसे भाजपा नेताओं के पास मोरारी बापू की कथा कराने का समय और पैसे भरपूर हैं पर जो मांग भाजपा ने अपने चुनावी वादों में की हैं उन्ही के लिए बच्चे लाठियां खा रहे हैं।

एक माह से चलने वाले इस धरने में भाजपा की छात्र विंग एवीबीपी के नेता नदारद हैं जबकि सत्ता में उन्ही की पार्टी है। ऐसा जान पड़ता है कि सभी काँवड ले कर आज तक वापस नहीं आये। विश्वगुरु बनाने के लच्छे फेकने वाले मोदी और ईमानदारी व पारदर्शिता का ढोंग पीटने वाले खट्टर के लिए ये शर्मनाक ही है की जो बिना मांगे मिलना चाहिए उसके लिए बच्चे धरना दें और बिना बात लाठियां भी खाएं।